



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 131 | नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 20, 1974/फाल्गुन 29, 1895

No. 131 | NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 20, 1974/PHALGUNA 29, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 20th March 1974

S.O. 183(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution and in supersession of all previous orders on the subject, the President hereby directs that the Administrators of all Union territories other than Arunachal Pradesh and Mizoram (whether known as Administrator, Chief Commissioner or Lieutenant Governor) shall, subject to the control of the President and until further orders, exercise the powers and discharge the functions under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), as mentioned in the Schedule hereto annexed, subject to the condition that the Central Government may itself exercise all or any of those powers and discharge all or any of those functions, should it deem necessary so to do.

2. This notification shall have effect from the 1st April, 1974.

SCHEDULE

Powers/functions

(1) All powers and functions of the State Government except those conferred by sections 8 and 477;

(2) (a) the powers and functions of the Central Government under sub-section (1) of section 197 and sub-section (4) of section 199, in respect of persons employed in connection with the affairs of the concerned Union territory;

Powers/functions

(b) the power of the Central Government under item (i) of the proviso to section 321 to permit the Public Prosecutor to withdraw from a prosecution, where the offence is against a law relating to a matter enumerated in List II or List III in the Seventh Schedule to the Constitution; and

(3) the powers and functions of the appropriate Government under section 432 except in respect of—

(a) cases, where the sentence is the sentence of death and has not been commuted;

(b) cases where the sentence is for an offence against any law relating to any of the matters enumerated in List I in the Seventh Schedule to the Constitution; and

(c) cases where the order referred to in sub-section (6) of section 432 is passed under any law relating to any of the matters enumerated in List I in the Seventh Schedule to the Constitution.

[No. U-11011/2/74-UTL-(i)]

गृह मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1974

का० आ० 183(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में और इस विषय पर सभी पूर्वतन आदेशों को अतिष्ठित करते हुए, यह निदेश देते हैं कि ग्रहणाचल प्रदेश और मिजोराम से भिन्न सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक (चाहे उनका नाम प्रशासक, मुख्य आयुक्त या उप-राज्यपाल हो), राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और जब तक और आदेश न हो, वण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन, जो इससे उपाबन्ध अनुसूची में उल्लिखित हैं, इस शर्त के अधीन करेंगे कि केन्द्रीय सरकार स्वयं उन सभी शक्तियों का या उन में से किसी का प्रयोग और उन सभी कृत्यों या उन में से किसी का निर्वहन कर सकेगी जिन्हें वह ऐसा करने के लिए आवश्यक समझे।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1974 से प्रभावी होगी।

अनुसूची

शक्तियां/कृत्य

(1) राज्य सरकार की उन शक्तियों और कृत्यों के सिवाय सब शक्तियों और कृत्य जो धारा 8 और 477 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं ;

(2) (क) सम्पूक्त संघ राज्य क्षेत्र के कार्यकलापों के सम्बन्ध में नियोजित व्यक्तियों की बाबत, धारा 197 की उपधारा (1) और धारा 199 की उपधारा (4) के अधीन केन्द्रीय सरकार की शक्तियां और कृत्य ;

(ख) जहां कोई अपराध संविधान की सप्तम अनुसूची में की सूची 2 या सूची 3 में प्रगणित किसी विषय से संबन्धित किसी विधि के विरुद्ध हो, वहां किसी अभियोग से प्रत्याहरण करने के लिए लोक अभियोजक को अनुज्ञा देने के लिए धारा 321 के परन्तुक की मद (i) के अधीन केन्द्रीय सरकार की शक्ति; और

शक्तियाँ/कृत्य

(3) निम्नलिखित मामलों के सिवाय धारा 432 के अधीन समुचित सरकार की शक्तियाँ और कृत्य :—

(क) ऐसे मामले जहाँ कोई दण्डादेश मृत्यु दण्डादेश हो और उसका लघुकरण न किया गया हो ;

(ख) ऐसे मामले, जहाँ कोई दण्डादेश किसी ऐसे अपराध के लिए हो जो संविधान की सप्तम अनुसूची में की सूची 1 में प्रगणित विषयों में से किसी विषय सम्बन्धित विधि के विरुद्ध हो ; और

(ग) ऐसे मामले, जहाँ धारा 432 की उपधारा (6) में निर्दिष्ट आदेश संविधान की सप्तम अनुसूची में की सूची 1 में प्रगणित विषयों में से किसी विषय से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन पारित किया गया हो ।

[सं० यू०-11011/2/74-यु० टी० एल०--(i)]

S.O. 184(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 1 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby applies to the Union territories of Arunachal Pradesh and Mizoram, being tribal areas within the meaning of the Explanation to the said proviso, with effect from the 1st day of April, 1974, the provisions of the said Code, as mentioned in column (1) of the Schedule hereto annexed, to the extent, and subject to the modifications, if any, specified in column (2) of the said Schedule.

SCHEDULE

Provision of the Code applied	Ext. of application and modification
(1)	(2)
Section 2	To the extent the definitions contained therein apply for the interpretation of the provisions extended by this notification and those contained in Chapters VIII, X and XI of the Code.
Section 3	After sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely:— “(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this section— (i) any reference in such of the provisions of this Code, as apply to the Union territories of Arunachal Pradesh and Mizoram, to the Court mentioned in column (1) of the Table below shall, until the Courts of Session and Courts of Judicial Magistrates are constituted in the said Union territories, be construed as references to the Court of Magistrate mentioned in the corresponding entry in column (2) of that Table.

1	2
TABLE	
(1)	(2)
Court of Session or Sessions Judge or Chief Magistrate	District Magistrate
Magistrate or the first class or Judicial Magistrate of the first class	Executive Magistrate
(ii) the functions mentioned in clause (a) of sub-section (4) shall be exercisable by an Executive Magistrate".	

Section 5

Sections 20 to 23

(both inclusive)

Chapter V

So much of this Chapter as applies to the arrest of any person belonging to one or more categories of persons specified in section 109 or 110.

Section 373

[No. U-11011/2/74-UTL-(ii)]

का० प्रा० 184(अ).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की 2) की धारा 1 की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अरुणाचल प्रदेश और मिजोराम संघ राज्य क्षेत्रों को, जो उक्त परन्तुक के राष्ट्रीकरण के अर्थ के भीतर जनजाति क्षेत्र हैं, उक्त संहिता के ऐसे उपबन्ध, जो इसके उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में उल्लिखित हैं, उस समा तक, और उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट उपांतरणों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल 1974 से लागू करता है।

अनुसूची

संहिता के उपबन्ध जो लागू होंगे	लागू किए जाने की सीमा और उपांतरण
(1)	(2)
धारा 2	उस समा तक जिस तक उसमें अन्तर्विष्ट परिभाषाएं, इस अधिसूचना द्वारा विस्तारित उपबन्धों और उन उपबन्धों के निर्वाचन के लिए लागू होती हैं जो संहिता के अध्याय 8, 10 और 11 में अन्तर्विष्ट हैं।
धारा 3	उपधारा (4) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी अर्थात् :— “(5) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी,— (i) इस संहिता के उपबन्धों में से किन्हीं ऐसे उपबन्धों में, जो अरुणाचल प्रदेश और मिजोराम संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होते हैं, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित न्यायालय के प्रति किसी निर्देश से, जब तक कि सेशन न्यायालय और न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय उक्त संघ राज्यक्षेत्रों में गठित न किए गए हों, उस सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थगनी प्रविष्टि में उल्लिखित मजिस्ट्रेट के न्यायालय के प्रति निर्देशों के रूप में अर्थ लगाया जाएगा।

(1)	(2)
मारणो	
(1)	(2)
सेशन न्यायालय या सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय।	जिला मजिस्ट्रेट
मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट	कार्यपालक मजिस्ट्रेट

(ii) उपधारा (4) के खण्ड (क) में उल्लिखित कृत्य किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोक्तव्य होंगे।

धारा 5

धारा 20 से 23 (जिनके

अन्तर्गत ये दोनों धारा

भी हैं)

अध्याय 5

इस अध्याय का उनका भाग जिसका धारा 109 या 110 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के एक या अधिक प्रवर्गों के किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए लागू होता है।

धारा 373

[सं० पृ०-11011/2/74-यू टी एल-(i)]

S.O. 185(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that, subject to his control and until further orders, the powers and functions of the State Government under clause (s) of section 2, sections 20, 21 and 22, sub-section (2) of section 108, clause (b) of sub-section (1) of section 132, sections 133, 134, 143 and 144 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) shall, in relation to the Union territory of Arunachal Pradesh or Union territory of Mizoram, be exercised and discharged also by the Administrator of that Union territory.

This notification shall come into force on the 1st day of April, 1974.

[No. U-11011/2/74-UTL-(iii)]

K. R. PRABHU, Addl. Secy.

का० प्रा० 185(अ)—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में, यह निर्देश देते हैं कि उनके नियंत्रण के अधीन रहते हुए और जब तक और आदेश न हों, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 2 के खण्ड (घ), धारा 20, 21 और 22, धारा

108 की उपधारा (2), धारा 132 की उपधारा (1) के खण्ड (ख), धारा 133, 134, 143 और 144 के अधीन राज्य सरकार की शक्तियों तथा कृत्यों का प्रयोग और निर्वहन, अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र या मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में उस संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा भी किया जायेगा।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1974 को प्रवृत्त होगी।

[सं० यू०-11011/2/74-यूटीएल (iii)]

के० आर० प्रभू, अपर सचिव।